



सबर्नी कॉपर, मैनेजिंग डायरेक्टर

पढ़ें भारत हर स्वर शक के साथ आज तक आमने-सामने

पंजाब, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली एवं हरियाणा

Email : aajtakaamnesaamne.in@gmail.com

RNI No-Punhin2013/54688

1-15 JULY-2025



एस. के. सुरेश, मुख्य संपादक

साल 2025 / संपादक एसके सक्सेना / www.aajtakaamnesaamne.com / Help Line 9878552070

दिल्ली के चाणक्यपुरी के नवी और द्वारका के स्कूल में बम खोने की घटना



नई दिल्ली (एजसी)–दिल्ली के दो स्कूलों में बम होने की सूचना मिली है। ये चाणक्यपुरी का नवी स्कूल और द्वारका के सीआरपीएफ स्कूल हैं। जहां बम होने की काला आई है, स्कूलों में बम होने की जानकारी ई-मेल के जरिए भेजी गई है। इसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। ये पुलिस एसके सक्सेना के द्वारा दिल्ली के चाणक्यपुरी के नवी और द्वारका के स्कूल में बम खोने की घटना

प्रदर्शन के लिए आये हैं। ये स्कूलों को देखते हुए स्कूल को खाली करा दिया गया है। इससे पहले भी कई स्कूलों में बम होने की घटना हुई थी, लेकिन अभी तक किसी भी स्कूल में कुछ संदिग्ध सामान नहीं मिला है। कई बार स्कूल के स्टूडेंट्स ही मजाक-मजाक में ऐसी झूमल कर देते हैं।

फेमस मॉडल सैन रेचल ने की आत्महत्या, पुलिस को मौके से मिला सुसाइड नोट

पुडुचेरी (एजसी)–पुडुचेरी से फेमस मॉडल सैन रेचल की खुदकुशी का मामला सामने आया है। पुलिस को शक है कि भारी कर्ज और तनाव के कारण उन्होंने ये कदम उठाया होगा। तहलीलदार ने जाच के आदेश दिए हैं क्योंकि सैन की पिछले साल ही शादी हुई थी। भौक से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, उसमें लिखा है कि उनकी मौत के लिए कोई ज़मिनदार नहीं है। वहीं जांकर्ताओं का कहना है कि सैन रेचल ने अपने काम के लिए पेसे जुटाने के लिए अपने गहने गिरवी रखे थे। अपनी प्रतिभा के दम पर मॉडलिंग जगत में सैन रेचल उर्जा शकर प्रिया ने रंग की पराइट किए बिना अंग वहन बनाई। वो पुडुचेरी के करमसी कुप्रम में रहती थीं। बताया जा रहा है कि किनी की सप्ताही के कारण पिछले कुछ दिनों में उनका खुदकुश लक्ष्य अस्त्वाल में उल्लंघन चल रहा था। इसी बीच, बताया जा रहा है कि उन्होंने आज अपने घर पर बड़ी मात्रा में ब्लड प्रेशर की गोलियां खाकर आमत्या कर ली। कहा जा रहा है कि कई फैशन शो आयोजित करने के दौरान हुए उल्लंघन के कारण उन्होंने आमत्या की होंगी। पुडुचेरी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाच कर रही है। 2020-2021 में मिस पांडिचेरी,

2019 में मिस डार्क क्लीन तमिलनाडु और उसी वर्ष मिस ब्रेट एटीट्यूड सहित कई खिताब जीत चुकीं रेचल ने लेकर ब्लैक ब्लूटी श्रौती में मिस वर्ल्ड का खिताब भी जीता है।

वेदांता ने भाजपा को दिया 97 करोड़ का चंदा, कांग्रेस को 10 करोड़

नयी दिल्ली, (एजसी) – अरबपति उद्योगपति अनिल अग्रवाल की खनन कंपनी वेदांत लिमिटेड द्वारा सत्तारुद्ध भाजपा को चंदा दिया 2024-25 में चार गुना बढ़कर 97 करोड़ रुपये रही। यह राशि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष में सिर्फ 26 करोड़ रुपये थी। कंपनी की ताजा वार्षिक रिपोर्ट उसने पिछले वित्त वर्ष में कुल 15.7 करोड़ रुपये का राजनीतिक वित्त वर्ष के अनुसार, एक तरह जाहा भाजपा को दिया गया चंदा चार गुना हो गया, वहीं मुख्य विपक्ष दल कांग्रेस को दिया गया चंदा घटक सिर्फ 10 करोड़ रुपये (इससे पिछले वित्त वर्ष में 15 करोड़ रुपये), जारखंड मुक्ति मोर्चा को 20 करोड़ रुपये (इससे पिछले वित्त वर्ष में पांच करोड़ रुपये) और कांग्रेस को 10 करोड़ रुपये (पिछले वित्त वर्ष में भी 49 करोड़ रुपये) का चंदा दिया।

नयी दिल्ली, (एजसी) – अरबपति उद्योगपति अनिल अग्रवाल की खनन कंपनी वेदांत लिमिटेड द्वारा सत्तारुद्ध भाजपा को चंदा दिया 2024-25 में चार गुना बढ़कर 97 करोड़ रुपये रही। यह राशि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष में सिर्फ 26 करोड़ रुपये थी। कंपनी की ताजा वार्षिक रिपोर्ट उसने पिछले वित्त वर्ष में कुल 15.7 करोड़ रुपये का राजनीतिक वित्त वर्ष के अनुसार, एक तरह जाहा भाजपा को दिया गया चंदा चार गुना हो गया, वहीं मुख्य विपक्ष दल कांग्रेस को दिया गया चंदा घटक सिर्फ 10 करोड़ रुपये (इससे पिछले वित्त वर्ष में 15 करोड़ रुपये), जारखंड मुक्ति मोर्चा को 20 करोड़ रुपये (इससे पिछले वित्त वर्ष में पांच करोड़ रुपये) और कांग्रेस को 10 करोड़ रुपये (पिछले वित्त वर्ष में भी 49 करोड़ रुपये) का चंदा दिया।

हिमाचल प्रदेश 10वीं, 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा का टाइम टेबल किया जारी

22 जुलाई से एग्जाम शुरू

उना (एजसी)–हिमाचल प्रदेश विद्यालयी शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की कम्पार्टमेंट और सुधार परीक्षाओं की डेटरी जारी कर दी है। ये परीक्षाएं 22 जुलाई से शुरू होकर एक ही सुधार के संत में, सुबह 8-45 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएंगी। 10वीं की परीक्षाएं 29 जुलाई तक चलेंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 28 जुलाई को समाप्त होंगी। आवेदन 10 जून से शुरू हो चुके हैं और बिना किसी लेट फाइन के 26 जून आवेदन जमा करने की लास्ट डेट है। इस परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स को 700 रु देना होगा। बोर्ड की ओर से

इस साल, 12वीं एवं परीक्षाओं से पता चला है कि मार्च में आयोजित परीक्षा में उपस्थित होने वाले 88.64 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं, जो पिछले अंकड़े 83.16 प्रतिशत के कंपोटर्स के सेट और मुताबिक, इस साल गणराज्य के सेट और पालक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की महक ने 97.2 प्रतिशत नवारों के साथ टॉप किया है। इसके अलावा, कुल 86,373 छात्रों में से 76,151 पास घोषित किए गए हैं, 3,838 को कंपार्टमेंट कैटग्रेजी में रखा गया है और 5,868 फैल हुए हैं। 17 मई को घोषित शुरुआती नवीनों में 71,591 छात्र पास हुए हैं, 5,847 कम्पार्टमेंट में और 8,581 अनुत्तीर्ण घोषित किए गए हैं।

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सभी नियमित, कम्पार्टमेंट, एकस्ट्रा वेबसाइट से डेटरी लेट फाइन के 26 जून आवेदन करने की लास्ट डेट है। इस कार्यक्रम का पालन करना होगा।

इस साल, 12वीं एवं परीक्षाओं से सोना देना होगा।

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सभी नियमित, कम्पार्टमेंट, एकस्ट्रा वेबसाइट से डेटरी लेट फाइन के 26 जून आवेदन करने की लास्ट डेट है। इस कार्यक्रम का पालन करना होगा।

इस साल, 12वीं एवं परीक्षाओं से सोना देना होगा।

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सभी नियमित, कम्पार्टमेंट, एकस्ट्रा वेबसाइट से डेटरी लेट फाइन के 26 जून आवेदन करने की लास्ट डेट है। इस कार्यक्रम का पालन करना होगा।

इस साल, 12वीं एवं परीक्षाओं से सोना देना होगा।

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सभी नियमित, कम्पार्टमेंट, एकस्ट्रा वेबसाइट से डेटरी लेट फाइन के 26 जून आवेदन करने की लास्ट डेट है। इस कार्यक्रम का पालन करना होगा।

इस साल, 12वीं एवं परीक्षाओं से सोना देना होगा।

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सभी नियमित, कम्पार्टमेंट, एकस्ट्रा वेबसाइट से डेटरी लेट फाइन के 26 जून आवेदन करने की लास्ट डेट है। इस कार्यक्रम का पालन करना होगा।

इस साल, 12वीं एवं परीक्षाओं से सोना देना होगा।

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सभी नियमित, कम्पार्टमेंट, एकस्ट्रा वेबसाइट से डेटरी लेट फाइन के 26 जून आवेदन करने की लास्ट डेट है। इस कार्यक्रम का पालन करना होगा।

इस साल, 12वीं एवं परीक्षाओं से सोना देना होगा।

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सभी नियमित, कम्पार्टमेंट, एकस्ट्रा वेबसाइट से डेटरी लेट फाइन के 26 जून आवेदन करने की लास्ट डेट है। इस कार्यक्रम का पालन करना होगा।

इस साल, 12वीं एवं परीक्षाओं से सोना देना होगा।

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सभी नियमित, कम्पार्टमेंट, एकस्ट्रा वेबसाइट से डेटरी लेट फाइन के 26 जून आवेदन करने की लास्ट डेट है। इस कार्यक्रम का पालन करना होगा।

इस साल, 12वीं एवं परीक्षाओं से सोना देना होगा।

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सभी नियमित, कम्पार्टमेंट, एकस्ट्रा वेबसाइट से डेटरी लेट फाइन के 26 जून आवेदन करने की लास्ट डेट है। इस कार्यक्रम का पालन करना होगा।

इस साल, 12वीं एवं परीक्षाओं से सोना देना होगा।

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सभी नियमित, कम्पार्टमेंट, एकस्ट्रा वेबसाइट से डेटरी लेट फाइन के 26 जून आवेदन करने की लास्ट डेट है। इस कार्यक्रम का पालन करना होगा।

इस साल, 12वीं एवं परीक्षाओं से सोना देना होगा।

जार

ਪ੍ਰਲਿੰਗ ਪੱਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬਿਆਂ ਕੇ ਹਿਤਾਂ ਕੇ ਰਿਵਲਾਫ-ਵਿਜਾਹ ਸਾਂਪਲ॥

पंजाब के शहरों को छोड़ ग्रामीण विरासत और संरकृति को बिना नुकसान पहुंचाए शहरी स्तर की सुविधाएं योजनाबद्ध तरीके से मुहैया करवाए आप सरकार-विजय सांपला

१८५) सप्तम

जिला अध्यक्ष सुरील शर्मा की अध्यक्षता में पूर्व केंद्रीय मंत्री व पूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने पंजाब सरकार की लैंड पुलिंग नीति के खिलाफ भूमि अधिग्रहण के अहम मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने इस मौके पर गंभीरता से पक्ष रखते हुए कहा कि यह नीति बड़े जमीन मालिकों और प्राइवेट डेवलपरों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है, जबकि छोटे किसानों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे पंजाब का किसान भी बर्बाद हो जाएगा, जिसके पास कोई अन्य आय का साधन नहीं बचेगा। और जब किसी प्रदेश की कृषि नीचे गिरती है, तो इसका असर आवाजाही, व्यापार से लेकर समाज के हर क्षेत्र पर पड़ेगा, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर देगा। उन्होंने कहा कि आज अपने खेतों का राजा पंजाब का किसान कल उसी के खेत में कटी कॉलोनी का गार्ड बनकर खड़ा होने के लिए मजबूर होगा विजय सांपला ने कहा कि इस लैंड पुलिंग योजना से पंजाब सरकार प्लॉट दिए जाने तक 30,000 रुपये प्रति एकड़ सालाना देगी। इससे किसान का नुकसान पहले दिन से ही



ता अपना ज़मान बच सकता ह आर न ही बैंक से इस पर ऋण ले सकता है। उन्होंने कहा कि इस नीति में एक एकड़ से कम ज़मीन वाले किसान को न तो ठेका मिलेगा और न ही कर्मशाल प्लॉट मिलेगा जिससे किसान और उसका परिवार बेरोज़गार हो जाएगा विषय सांप्ला ने कहा कि किसान एक साल में तीन फ़सलें लगाकर औसतन 2 लाख रुपये सालाना मुनाफ़ा कमाता है। फिर सरकार द्वारा दिए 30,000 रुपये

त एकड़/सालाना से उसका क्या आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की दमनकारी नीति प्रदेश के 200 गांवों में से 158 गांवों की 0,000 एकड़ से अधिक जमीन निशाना बना रही है जोकि बिल्कुल तलत है। उन्होंने कहा कि जालंधर की गभग 1,000 एकड़ भूमि धिग्हण करके सरकार गरीब सान के साथ अत्याचार कर रही उन्होंने कहा कि पंजाब में पहले ही 2ब से अधिक शहरीकृत है और

बद्यन क लिए गति रस्ते इस्तेमाल किया है इससे किसानों व उनकी जमीनों के उचित मूल्य वंचित कर दिया गया और प्रभावित परिवारों को उनकी जमीनों का उचित मुआवजा, पारदर्शिता और उचित पुनर्वास जैसे महत्वपूर्ण अधिकारों वंचित कर दिया गया उन्होंने कहा कि इस नीति से पंजाबी विरासत विनाश और पंजाब का असली अंदर एकमात्र पूँजी, पंजाब की आत्मा, यह के गांव, खेत, सथान, पश्च धन ही हैं। अगर यहां की जमीनें ही नहीं रहें और यहां कंक्रीट के जगल ही बढ़ दिए गए, तो हमारा समृद्ध पंजाब विरासत कैसे जीवित रहेगा? उन्होंने कहा कि पंजाब को और शहरों व नहीं बल्कि ग्रामीण विरासत, संस्कृति को बिना नुकसान पहुँचाए, यहां शहर स्तर की सुविधाएं योजनाबद्ध तरीके से मुहैया करवाकर विकास करने वाला आवश्यकता है इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील शर्मा, प्रदेश महामंत्री राकेश राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष केढ़ी भंडारी, पूर्व विधायक जगबांध बराड़, जिला महामंत्री अशोक सर्से हिक्की, राजेश कपूर, अमरजीत सिंह गोलड़ी, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश शर्मा, जिला प्रवक्ता शनी शर्मा, गोविंद राय, दीवान अमित अरोड़ा आउपस्थित थे।



ਪੱਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਵਗਤ ਹਿੱਸ਼ਿਆਂ ਕੋ ਸ਼੍ਰਦ਼ਧਾਂਜਲਿ ਮੰਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿ

आज विधान सभा के पिछले सैशन के बाद दिवंगत हुई हस्तियों सहित अहमदाबाद हवाई जहाज़ हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि भेट की। 16वीं पंजाब विधान सभा के 9वें (विशेष) सैशन के दौरान सदन ने तरन तारन के विधायक डा. कश्मीर सिंह सोहल, पूर्व केंद्रीय मंत्री स. सुखदेव सिंह ढीड़सा,

कैबिनेट मंत्री ने ई.एस.आई. अस्पताल का ऑचक निरोक्षण किया

सरकार की 10 लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा योजना को ऐतिहासिक कदम बता

लागा फूल
त करने

परापर शुगांकता करने के उद्देश्य से, पंजाब के बागवानी, स्वतंत्रता सेनानी और रक्षा सेवा कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत ने आज स्थानीय ई.एस.आई. अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर, कैबिनेट मंत्री ने ओ.पी.डी., इमरजेंसी विभाग, आंखों, हड्डियों, दांतों, मेडिसन, सर्जरी विभाग सहित विभिन्न विभागों का दौरा किया और अस्पताल में मरीजों को उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने वार्डों में भर्ती मरीजों से भी बातचीत की और अस्पताल में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में



मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व क्षेत्र को प्राथमिकता दी है और स्वास्थ्य

करने के पांच तरकार के फुलों
ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने दे
कि इससे बड़ी संख्या में लोग उच्च
गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं
लाभ उठा सकेंगे। विशेषकर वे ले
जो आर्थिक तंगी के कारण अब
इलाज नहीं करवा पाते। श्री भगत
कहा कि इस योजना को बिना किसी
पक्षपात्र के लागू करके यह सुनिश्चि
किया जाएगा कि राज्य के हर
को एक स्वास्थ्य कार्ड प्रदान वि
जाए। इस अवसर पर मैडिकल
सुपरडेंट डा. वंदना, डा. नमिता और
डा. विश्वास लृथरा और अस्पताल
अन्य स्टाफ भी मौजूद था।

मुख्यमंत्री द्वारा पंजाब का सिंधु नदी के जल में से न्यायालंबित हिस्सा देने की माग

पंजाब के पास किसी अन्य राज्य का दन का लिए आतारक्त पाना नहा, दश के लिए दी गई कुर्बानियों और योगदान के बदले पंजाब का हक् और भी बढ़ जाता।

— इ दिल्ली, —मुख्यमंत्री —

सिंह मान ने आज फिर स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंजाब के पास किसी अन्य राज्य को देने के लिए एक बूँद भी अतिरिक्त पानी नहीं है। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने सिंधु नदी के पानी में हिस्सा मांगने के साथ-साथ सतलुज यमुना लिंक (एस.वाई.एल.) नहर के बजाय यमुना सतलुज लिंक (वाई.एस.एल.) नहर का विचार भी प्रस्तुत किया। आज यहां श्रम शक्ति भवन में एक बैठक में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पंजाब के पास किसी अन्य राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है, इसलिए एक बूँद भी साझा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने फिर कहा कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है और अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार राज्य में पानी की उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन कराने पर उपनाव लिया जाना चाहिए और पश्चिमी नदियों से पानी लाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ताकि पानी की मांग को पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित करने के अवसर का उचित उपयोग किया जाना चाहिए ताकि राज्य की पानी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के हालिया फैसले ने भारत से सटी पश्चिमी नदियों (सिंधु, जेहलम और विनाब) से पानी का अधिकतम उपयोग करने की बड़ी संभावनाएं पैदा की हैं। इस दोहराने के बाद भारत सिंह मान ने कहा कि पंजाब इस समय भूजल के गिरते स्तर की समस्या से जूझ रहा है, इसलिए राज्य को नदी जल के उपयोग, प्रवाह और वितरण के लिए भविष्य की रणनीतियों में प्राथमिकता दी जानी



निमाण के मुद्दे को टाला जा सकता है और इसे हमेशा के लिए त्याग दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा

A photograph of a man with a beard, wearing a yellow turban and a pink and white checkered jacket over a white shirt. He is seated at a desk with a small microphone and a box of 'Milkmaid' butter. In the background, there is a framed portrait of a man and some greenery. The man is gesturing with his hands while speaking.

हरियाणा और राजस्थान का भुगतना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एस.वाई.एल नहर लिए आज तक जमीन भी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि तेज नदियों के 34.34 एमएफ पार्क में से पंजाब को केवल 14.2 एमएफ पानी आवंटित किया गया था, जो 40 प्रतिशत है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि बाकी 6 प्रतिशत हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान को आवंटित किया गया था, हालांकि इनमें से कोई भी नवास्तव में इन राज्यों से होकर नहीं बहती।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को पहले ही पंजाब की रावी, ब्यांकी और सतलुज नदियों से कुल 5.95 एमएफ (रावी-ब्यास) 1.62 एमएफ और सतलुज 4.33 एमएफ) पानी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि रावी, ब्यांकी और सतलुज के अलावा हरियाणा को यमुना से 4.65 एमएफ और शारदा यमुना लिंक के माध्यम से शारदा से 1.62 एमएफ पानी मिल रहा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि नहरी पानी की कमी कारण पंजाब में भूजल विनिर्भरता बढ़ी है, जिसके कारण पंजाब के कुल 153 में से 11 जोन (75 प्रतिशत) को अत्यधिक पानी निकालने वाला घोषित किया गया है, जबकि हरियाणा के केवल 61 प्रतिशत (143 में से 85 जोन में ही अत्यधिक पानी निकाला जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब

आधिक को वृद्धि हुई है। उन्हाने कहा कि पंजाब में देश की तुलना में 157 प्रतिशत अधिक पानी भूजल से निकाला जाता है, जो राजस्थान (150 प्रतिशत) से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि पंजाब ने अपनी जरूरतों को भी नजर अंदर रखा किया और 60 प्रतिशत पानी गैर-रिपेरियन राज्यों को दे दिया, जहां से रावी-ब्यास और सतलज नदियां गुजरती भी नहीं हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने 2024 के दौरान देश के अनाज भंडार में 124.26 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया, जो भारत भर में 47 प्रतिशत है, जबकि पंजाब केंद्रीय पूल में 24 प्रतिशत चावल भी देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की पानी की कुल आवश्यकता 52 एमएफ है और राज्य को सभी खेतों से केवल 26.75 एमएफ पानी मिलता है, जिसमें 12.46 एमएफ नहरी पानी और 14.29 एमएफ भूजल है। उन्होंने कहा कि पंजाब की नदियों का पानी पड़ोसी राज्यों के साथ बांटा गया है, जबकि बाढ़ के समय नुकसान के बाढ़ के समय नुकसान के बाढ़ के समय होता है, जिससे हर साल पंजाब पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि जब पड़ोसी राज्यों के साथ तय सीमा के अनुसार पानी बांटा जाता है, तो बाढ़ के कारण होने वाली तबाही के लिए भी पड़ोसी राज्यों को पर्यावरणीय बदलावों के सदभू में समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मानक भी हर 25 साल बाद समीक्षा के लिए बाध्य करते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे हरियाणा रावी-ब्यास के पानी पर अपना हक समझता है, वैसे ही पंजाब यमुना के पानी पर अपना हक समझता है, क्योंकि भारत सरकार के सिंचाई आयोग की 1972 की रिपोर्ट में पंजाब को यमुना नदी का रिपेरियन राज्य बताया गया है। भगवंत सिंह मान ने अफसोस जताया कि भारत सरकार का तर्क है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम-1966 यमुना नदी के बारे में चुप है, क्योंकि इन पानी को पंजाब और हरियाणा के बीच बांटने योग्य नहीं माना गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी तरह यह अधिनियम रावी के पानी के बारे में भी चुप है। उन्होंने कहा कि पंजाब ने पहले ही रावी-ब्यास के अतिरिक्त पानी के संबंध में 1981 में बने समझौते को रद्द कर 'पंजाब समझौता रद्द अधिनियम, 2004' के तहत निरस्त कर चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य ने 'पंजाब समझौता रद्द अधिनियम, 2004' की धारा-5 के तहत रावी-ब्यास के पानी के हरियाणा द्वारा उपयोग को बरकरार किया। भगवंत सिंह मान ने बताया कि पंजाब से पाकिस्तान की ओर कोई पानी नहीं छोड़ा जा रहा और पाकिस्तान में जो पानी

